

# कच्चे माल की कमी से धरे रह गए टायर कंपनियों के अरमान

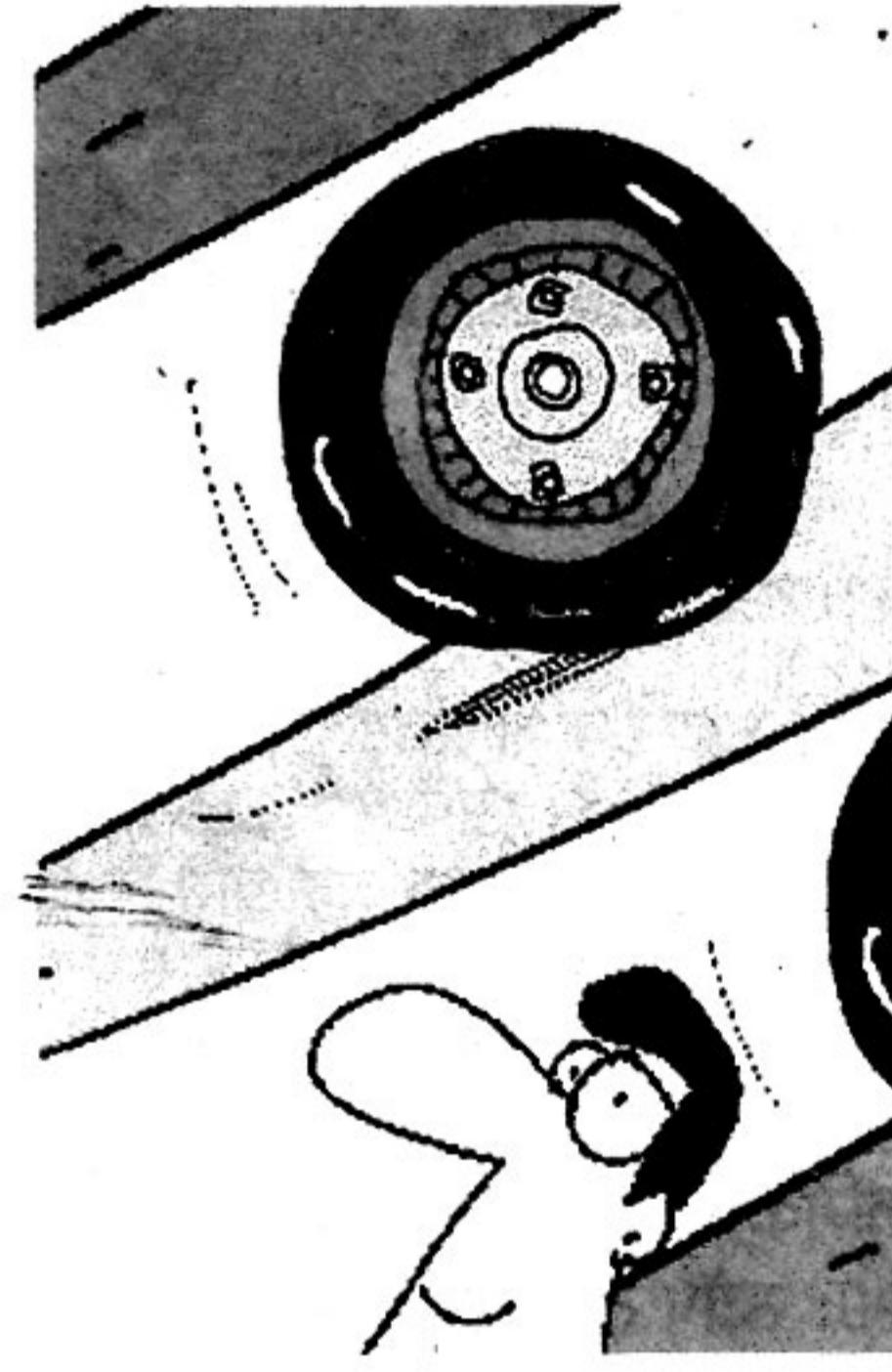
[कृष्णकुमार पीके | कोच्चि]

नेचुरल रबड़ के दाम में कमी और टायर के आयात में गिरावट के बावजूद टायर कंपनियां ग्राहियों की बिक्री बढ़ाने का फायदा नहीं उठा पा रही हैं क्योंकि उन्हें कार्बन ब्लैक, रबड़ केमिकल्स और बीड वायर्स की पर्याप्त सप्लाई नहीं मिल रही है। एक टायर बनाने की जितनी लागत आती है, उसमें नेचुरल रबड़ का योगदान 35-40 परसेंट होता है। इसलिए नेचुरल रबड़ के दाम में आई कमी टायर कंपनियों के लिए अच्छी खबर है। कार और बाइक की बिक्री बढ़ाने से भी उनका बिजनेस बढ़ाना चाहिए। हालांकि, ऐसा हो नहीं रहा है।

इस बारे में जेके टायर के वाइस प्रेसिडेंट (मैटीरियल्स) आशीष पांडे ने बताया, 'कार्बन ब्लैक की कीमत काफी बढ़ी है। इसके साथ रबड़ केमिकल्स और स्टील बीड वायर्स की कमी का भी सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हम मार्केट में बढ़ती डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे हैं।' इन

तीनों कंपनियों की टायर के कच्चे माल में 25-30 परसेंट कार्बन ब्लैक, रबड़ हिस्सेदारी होती है। पांडे ने बताया, 'कच्चे माल में कमी की वजह से टायर इंडस्ट्री को प्रॉडक्शन में कटौती करनी पड़ रही है।' इंडस्ट्री की इस दिक्कत का हल आने वाले कुछ महीनों में निकलने की संभावना नहीं है। टायर कंपनियों ने कार्बन ब्लैक की कमी का मामला सरकार के सामने भी उठाया

है। टायर कंपनियों ने कार्बन ब्लैक से एंटी डंपिंग इयूटी हटाने और इसके आयात की इजाजत देने को कहा है ताकि इसकी सप्लाई बढ़ सके। डिमांड के मुकाबले सप्लाई कम होने से कार्बन ब्लैक की कीमत में 50 परसेंट की बढ़ोतरी हुई है। ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल राजीव बुद्धराजा ने कहा,



'सरकार ने एंटी-डंपिंग इयूटी के मिडटर्म रिव्यू का वादा किया है, लेकिन इसमें करीब 6 महीने का समय लग सकता है।' उन्होंने

बताया कि कार्बन ब्लैक की सप्लाई 30-35 परसेंट तक कम है। इस वजह से टायर यूनिट्स नेचुरल रबड़ के दाम में कमी का फायदा नहीं उठा पाई है। पिछले एक महीने में इसके दाम में 4 परसेंट की गिरावट आई है। आरएसएस 4 किस्म की रबड़ का दाम 120 रुपये प्रति किलो चल रहा है, जबकि आयातित ब्लॉक रबड़ की कीमत 90 रुपये प्रति किलो है। बुद्धराजा ने

कहा कि कार्बन ब्लैक की सप्लाई कम होने से लोकल मार्केट में रबड़ की बिक्री घट गई है। देश में ट्रक और बस रेडियल टायरों का आयात भी कम हुआ है। खासतौर पर एंटी-डंपिंग इयूटी लगाए जाने से चीन से इसके आयात में कमी आई है। बुद्धराजा ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में इनके आयात में 40 से 50 परसेंट की गिरावट देखी गई है।